TE|SF India

शिक्षा, आजीविका और स्वास्थ्य पर कोविड-19 का असर

iihs INDIAN INSTITUTE FOR HUMAN SETTLEMENTS

इस शोध में ये समझने का प्रयास किया गया है कि महामारी से (i) स्कूली शिक्षा - विद्यार्थियों, अध्यापकों और अभिभावकों; (ii) उच्च शिक्षा - विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं और फैकल्टी सदस्यों; तथा (iii) अनौपचारिक मजदूरों की आजीविका और दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़े हैं।

स्कूली शिक्षा

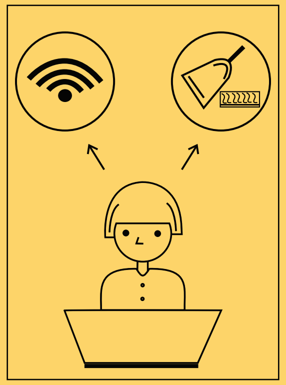

विद्यार्थी

अचानक ऑनलाइन क्लासेज़ शुरू हो जाने से समाज के कमज़ोर तबकों के बहुत सारे बच्चे लर्निंग की प्रक्रिया से बाहर छूट गये हैं क्योंकि उनके पास पर्याप्त संख्या में डिजिटल उपकरण और अच्छा इंटरनेट कनेक्शन प्रायः नहीं होता।

ऑनलाइन शिक्षा व संवाद में समय की सीमा और पाठ्यचर्या में काट-छांट से ऑनलाइन कक्षाओं के ज़रिये सीखने की संभावनाएं कुंद हुई हैं।

बहुत सारी लड़कियों को ऑनलाइन क्लासेज़ के बजाय घर के कामों में भी व्यस्त रखा गया। महामारी के कारण पैदा हुए आर्थिक संकट की वजह से बहुत सारी लड़कियों की वक्त से पहले ही शादी कर दी गयी है।

अध्यापक

अध्यापकों पर भी ऑनलाइन क्लासेज़ की सफलता सिद्ध करने के लिए लगातार दबाव रहा है। उन्हें मजबूर किया गया है कि वे सार्थक शिक्षा के बजाय केवल क्लासेज़ में हाजिरी और सहभागिता बढ़ाने पर जोर देते रहें।

महामारी ने अध्यापकों की ज्ञानशास्त्रीय पहचान और पेशेवर निर्णय क्षमता को और कमज़ोर कर दिया है। अब उन्हें दूसरी संस्थाओं व लोगों द्वारा तैयार की गयी टीचिंग-लर्निंग सामग्री को बच्चों तक पहुंचाने का साधन भर मान लिया गया है।

सरकारी प्राइमरी स्कूलों के बहुत सारे अध्यापक-अध्यापिकाओं को कोविड-१६ संबंधी ज़िम्मेदारियों में भी झोंक दिया गया जिससे उनके सामने नये खतरे पैदा हुए और बहुत सारे अध्यापकों की मृत्यु भी हुई है। कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले बहुत सारे अध्यापकों को महामारी के दौरान नौकरी से निकाल दिया गया।

अध्यापिकाओं को अपनी पेशेवर ज़िम्मेदारियों और घरेलू कामों के बीच संतुलन के साथ-साथ खुद अपने बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा की चुनौतियों से भी जूझना पड़ा जिससे वे गहरे तनाव में दिखायी पड़ती हैं।

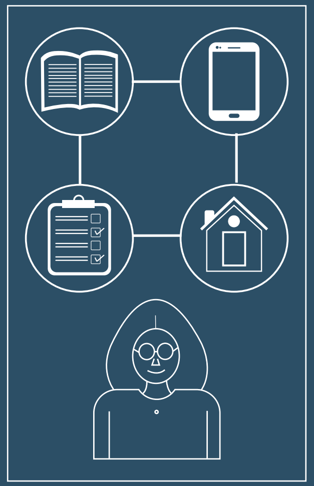

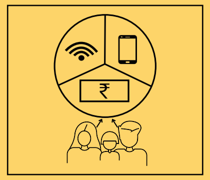

अभिभावक

रोज़गार और आमदनी खत्म हो जाने से बहुत सारे अभिभावक बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा के लिए मोबाइल फोन और इंटरनेट सुविधा मुहैया नहीं करा पाए।

स्कूल बंद होने के बावजूद अभिभावकों पर प्राइवेट स्कूलों की फीस चुकाने के लिए दबाव डाला गया जिसने उनको गहरे आर्थिक और मानसिक तनाव में ढकेल दिया है।

व्यवस्थागत प्रभाव

बहुत सारे सस्ते प्राइवेट स्कूल आर्थिक संकट का सामना नहीं कर सके और बंद हो गये हैं जिससे सरकारी स्कूलों में दाखिलों में इज़ाफ़ा हुआ है।

गैरसरकारी क्षेत्र, खासतौर से प्राइवेट आईटी कंपनियों के लिए ये महामारी ई-लर्निंग सामग्री व उत्पादों की बिक्री के ज़रिये बेतहाशा मुनाफ़े का मौका साबित हुआ है।

सरकारी स्कूली शिक्षा व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण

महामारी ने स्कूली शिक्षा व्यवस्था में मौजूद गहरी दरारों को उजागर कर दिया है। इसने पहुंच के सवाल को एक बार फिर सामने ला दिया है जबकि सरकार डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स पर जोर दे रही है और नये किस्म की बेदखली पैदा हो रही है।

इस 'लर्निंग क्राइसिस' को सिर्फ 'लर्निंग क्षति' के रूप में ही नहीं देखा जाना चाहिए। हमें इस पर व्यापक दृष्टि से सवाल उठाना चाहिए क्योंकि डिजिटल लर्निंग ने दिखा दिया है कि वर्ग, जाति, जेंडर, भाषा और क्षेत्र के धरातल पर हम भारी असमानताओं से जूझ रहे हैं।

सस्ते निजी स्कूलों के बड़ी तादाद में बंद हो जाने और सरकारी स्कूलों के दाखिलों में भारी इज़ाफ़े को सरकारी स्कूल व्यवस्था को पुनर्जीवित करने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए।

उच्च शिक्षा

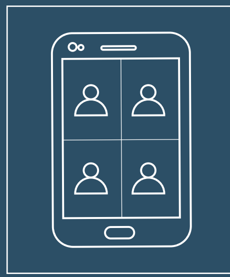

पहुंच

ऑनलाइन क्लासेज़ अटेंड करने की ज़िम्मेदारी केवल विद्यार्थियों के ऊपर थी जिससे उनके लिए उच्च शिक्षा का खर्चा और बढ़ गया है। ऐसे में समाज के वंचित तबकों, हाशियाई समुदायों और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए शिक्षा की संभावनाएं और क्षीण हो गयी हैं।

साधनसंपन्न निजी संस्थानों ने ऑनलाइन क्लासेज़ की दिशा में बदलाव को सहज बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के डिजिटल प्लेटफार्म्स का सहारा लिया जबकि सरकारी संस्थान इस तरह के प्रयास नहीं कर पाए जिसकी वजह से बहुत सारे विद्यार्थी लर्निंग प्रक्रिया से बाहर छूटते चले गये।

टीचिंग एवं लर्निंग

डिजिटल लर्निंग की वजह से क्लास के भीतर होने वाली सहभागिता में गिरावट आयी और फ़ैकल्टी विद्यार्थियों की लगन व उत्साह पर भी असर पड़ा।

प्रयोगशालाओं और पुस्तकालयों के बंद होने तथा फ़ील्डवर्क रुक जाने से शोध एवं व्यवहार आधारित लर्निंग पर भारी प्रभाव पड़ा है।

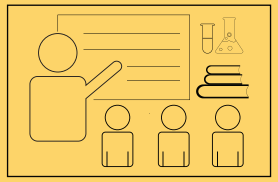

स्वास्थ्य

लंबे समय तक घर पर रहने के आदेशों तथा ऑनलाइन क्लासेज़ अटेंड करने में पेश आने वाली रुकावटों से विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है।

घर पर रहने की वजह से घर के कामों और परिजनों की देखभाल का ज़िम्मा अधिकांशतः महिलाओं पर आ गया है जिससे उनकी उत्पादकता पर असर पड़ा है। कई छात्राओं पर शादी का दबाव पड़ने लगा जिसके चलते उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी।

सामाजिक बेदखली एवं उच्च शिक्षा का कॉमोडिफिकेशन

उच्च शिक्षा में बेदखली की समस्या केवल भौतिक एवं डिजिटल पहुंच की समस्या नहीं है। दरअसल उच्च शिक्षा की पूरी संरचना ही संपन्न तबकों के पक्ष में झुकी दिखायी देती है।

उच्च शिक्षा को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित तबकों की पहुंच में लाने के लिए सरकारी व्यय बढ़ाना होगा। डिजिटल लर्निंग का आर्थिक भार विद्यार्थियों पर न पड़े, इसके लिए भी सरकार को अपना व्यय बढ़ाना होगा।

महामारी के दौरान लंबे समय तक अलगाव में रहने की वजह से जो भावनात्मक कठिनाइयां पैदा हुई हैं, उनको संबोधित करना जरूरी है। ये हस्तक्षेप डिजिटल लर्निंग के लिए आवश्यक तकनीकी सुविधाओं से कहीं ज़्यादा व्यापक होने चाहिए।

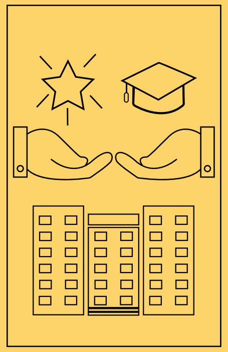

आजीविका

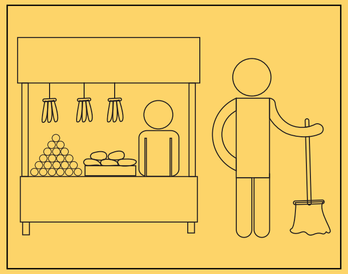

अनौपचारिक मज़दूरों की आजीविका और जीवन

महामारी ने अनौपचारिक क्षेत्र मज़दूरों की आजीविका के नाजुक स्वरूप को बेपर्दा कर दिया है। उनकी तनख़्वाह कम होती है, वे सुरक्षा प्रावधानों के अभाव में कठोर शारीरिक श्रम करते हैं।

महामारी के दौरान मज़दूरों की असुरक्षा - आर्थिक (आमदनी और आजीविका का अभाव), भौतिक (सस्ते मकानों का अभाव), और सामाजिक (जाति, काम पर आधारित भेदभाव) - न केवल खुलकर सामने आ गयी बल्कि और सघन हुई है।

संकट से निपटने के तरीके और राहत प्रयास

कर्जा लेना, कीमती चीज़ों को रेहन रखना, कोई नया काम ढूंढने जैसे स्वयं सहायता प्रयास तथा भोजन, आर्थिक सहायता और कोविड-१६ स्वास्थ्य जागरूकता जैसे कार्यक्रम फायदेमंद रहे हैं मगर ये अल्पकालिक उपाय हैं।

मगर ये अल्पकालिक उपाय नाकाफ़ी साबित हुए हैं क्योंकि उन्होंने भावी आर्थिक व भौतिक असुरक्षाओं को और ज़्यादा बढ़ा दिया।

खाद्य राशन और आर्थिक मुआवजा देने के लिए शुरू किये गये सरकारी राहत प्रयास निश्चित मानकों पर आधारित थे और अपनी संरचनात्मक खामियों और कठोर पात्रता कसौटियों की वजह से समावेशी नहीं बल्कि बेदखली पर आधारित थे।

गैरसरकारी प्रयासों में बड़े पैमाने के राहत कार्यों के लिए ज़रूरी संसाधनों का साफ अभाव पाया गया।

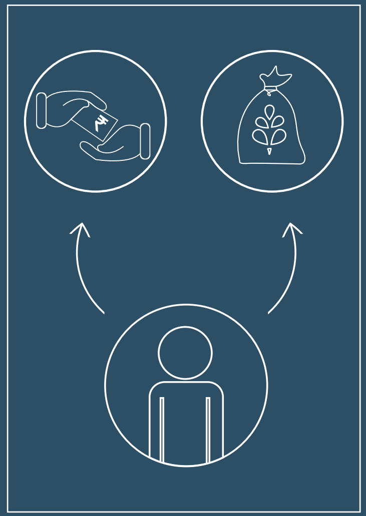

सामाजिक सुरक्षा उपायों की पुनर्कल्पना

महामारी जैसी आपात स्थितियों में व्यापक पीड़ा पर अंकुश लगाने के लिए हमें अपनी नीतियों को नये ढंग से सोचना होगा और उन्हें प्रभावित लोगों के लिए भोजन, नकद सहायता और आजीविका बहाली के उपायों पर केंद्रित करना होगा।

असुरक्षित लोगों और उनकी जगहों का विस्तृत रिकॉर्ड तैयार करना होगा ताकि उन तक पहुंचने के लिए उचित व्यवस्था विकसित की जा सके। इसके लिए मौजूदा और 'नयी' सामाजिक पंजिकाएं तैयार की जा सकती हैं।

सामाजिक सुरक्षा उपायों की रूपरेखा को जटिल, आपस में जुड़ी और परिवर्तनशील असुरक्षाओं के बहुआयामी रूप को ध्यान में रखते हुए नये सिरे से निर्धारित करना होगा।

https://www.tesfindia.iihs.co.in/resources/

[1]Batra, P., Bazaz, A., Shanmugam, A.,Ranjit, N., Kaur, H. and Das, R. (2021). Impact of the COVID-19 Pandemic on Education, Livelihoods and Health. Bengaluru: TESF India, IIHS DOI: https://doi.org/10.24943/ICPELHI08.2021